अरुण कुमार त्यागी के संमुख, जे.

फूल सिंह-अपीलार्थी

बनाम

विरेन्द्र सिंह और अन्य का प्रतिवादीगण एफ. ए. ओ. No.363-2012 को

13 मार्च, 2019

ए. मोटर वाहन अधिनियम, **1988**-धारा **166**-सिविल प्रक्रिया संहिता-आदेश **41** नियम **33**-अंशदायी लापरवाही-ट्रिपल राइडिंग-कोई क्रॉस अपील या आपत्तियां नहीं-मुआवजे को कम नहीं किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी अपील या प्रति-आपत्तियों के अभाव में अंशदायी लापरवाही और मुआवजे के परिणामी विभाजन के प्रश्नों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है और दावेदार को देय मुआवजे को सी. पी. सी. के आदेश 41 नियम 33 में पुनः प्रक्रिया द्वारा कम नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 30)

B. मोटर वाहन अधिनियम, **1988-Ss.128 (1),177.** अंशदायी लापरवाही-ट्रिपल राइडिंग चाहे अंशदायी लापरवाही हो-बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है।प्रचलित कानूनी स्थिति पर निर्णय लेने की अपील-टकटकी निर्णय का सिद्धांत-अपने आप में ट्रिपल राइडिंग, अंशदायी लापरवाही नहीं है**S**।

इसके अलावा यह भी माना गया कि अन्यथा जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या दो सवारों को ले जाना अपने आप में अंशदायी लापरवाही है या नहीं।एम. वी. अधिनियम की धारा 128 (1) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें दो पहियों वाली मोटर साइकिल के चालक को अपने अलावा एक से अधिक व्यक्तियों को ले जाने से प्रतिबंधित किया गया है, मोटर साइकिल पर दो सवारों को ले जाना एम. वी. अधिनियम की धारा 177 के तहत दंडनीय अपराध है। हालांकि, यह सवाल कि क्या यह अंशदायी लापरवाही है,िववाद मुक्त नहीं है।

2011 के एफ. ए. ओ. No.3760 में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बनाम बलविंदर सिंह ने 26.05.2011 फैसला हुआ

इस न्यायालय की समन्वित पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि दोपहिया वाहन पर तीन सवारी अंशदायी लापरवाही नहीं है।हालांकि, एफ. ए. ओ. में

2010 का सं**. 6550** जिसका शीर्षक अँग्रेजो देवी और अन्य बनाम जय प्रकाश ।

और अन्य लोगों 23.05.2012 और माननीय समन्वय पीठ पर निर्णय लिया

इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि ट्रिपल राइडिंग अपने आप में

अंशदायी लापरवाही है।माननीय निर्णय हुआ के विचारों के इस भिननता को देखते हुए

मामला बड़े न्यायालय को भेजा गया था k इस न्यायालय की एक माननीय समन्वय पीठ ने दिनांक 7.3.2014 के आदेश के माध्यम से पिरत किया

जो **2012** (ओ एंड एम) के एफ**.** ए**.** ओ**. No.2218** में शीरषक सोना देवी

और अन्य बनाम रमेश कुमार और अन्य।हालांकि, निर्णय

वृहद न्यायपीठ के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के कारण वर्तमान अपील को स्थगित नहीं किया जा सकता है और अपील का निर्णय सिद्धांत के अनुसार प्रचलित कानूनी स्थिति के आधार पर किया जाना है।

2011 के एफ. ए. ओ. No.3760 में जिसका शीर्षक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ।

बनाम हरजिंदर सिंह ने 26.05.2011 इस निर्णय पर निर्णय लिया

बाध्यकारी पूर्ववर्ती तब तक जब तक कि इसे एक बड़ी पीठ द्वारा खारिज नहीं किया जाता है और दोपहिया वाहन पर ट्रिपल सवारी अपने आप में अंशदायी लापरवाही नहीं होगी।बिना गाड़ी लाइसेंस गाड़ी चलाने के संबंध में इसी तरह के प्रश्न पर

सरस्वती पलारिया बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस में लाइसेंस बढ़ाया गया

कंपनी लिमिटेड **2019** एसीजे **42** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि

वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना चालक को दंडात्मक दायित्व के लिए उजागर कर सकता है लेकिन उस आधार पर अंशदायी लापरवाही का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(पैरा 31)

राज कपूर मलिक, अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए।

अश्विनी तलवार, अधिवक्ता और जगजीत सिंह चतरथ, अधिवक्ता

प्रतिवादी No.3-बिमा कंपनी के लिए।

अरुण कुमार त्यागी, जे।

(1) मृतक राकेश कुमार के पिता दावेदार ने दिए गए मुआवजे को बढ़ाने के लिए वर्तमान अपील दायर की जो।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, कैथल (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा एम. ए. सी. टी. में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2011

मामला सनखया **51** साल **2010** फूल सिंह बनाम विरेंद्र सिंह और अन्य के रूप में शीर्षक

25.03.2010 पर हुई मोटर वाहन दुर्घटना में घायल होने के कारण राकेश कुमार की मृत्यु।

(2) दावेदार ने उपरोक्त दावा याचिका दायर की

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 (संक्षेप में 'M.V.Act')

इस कथन पर कि 25.03.2010 पर जब राकेश कुमार पंजीकरण No.HR-08C-6697 वाली मोटरसाइकिल पर विक्रम और तारसेम के साथ पिछलि सवारि के रूप में गाँव कलायत से गाँव बरसिकिरी कला आ रहे थे, तो महिंद्रा पिक-अप पंजीकरण No.HR-64-3629, जो उतरवादी संख्या 2 के स्वामित्व में था और उतरवादी संख्या 3 के साथ बीमित था, जिसे उतरवादीफूल सिंह बनाम विरेंद्र सिंह और अन्य ।

प्रतिवादी नंबर 1 चला रहा था ने जल्दबाजी और लापरवाही से गलत तरफ आकर अपनी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वे नीचे गिर गए और

घायल हो गए ।दुर्घटना में घायल राकेश कुमार ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया ।एफ. आई. आर. No.39 दिनांक 25.03.2010 कैथल जिले के पुलिस स्टेशन कलायत में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304-ए के तहत दर्ज की गई थी ।मृतक की आयु लगभग 22 वर्ष थी और वह 5,157/- रुपये कमा रहा था ।स्वयं को मृतक का आश्रित और कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए, मृतक के दावेदार-पिता ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के खिलाफ लागत और ब्याज के साथ मुआवजे का पुरस्कार देने की मांग की।

(3) प्रतिवादीगण द्वारा याचिका का विरोध किया गया था ।अपने लिखित बयान में, प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 ने दुर्घटना और अपने दायित्व से इनकार किया। अपने लिखित बयान में, प्रतिवादीगण संख्या 3 ने प्रतिवादीगण संख्या 1 के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने, प्रतिवादीगण संख्या 2 के पास वैध परमिट नहीं होने और दावेदार द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 की मिलीभगत से दावा याचिका दायर किए जाने के बारे में आपत्तियां लीं ।प्रत्यर्थी संख्या 3 ने भी याचिका में किए गए कथनों का खंडन किया और इसके दायित्व से इनकार किया।

(4) न्यायाधिकरण ने मुद्दों को तैयार किया और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्षय को दर्ज किया ।अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन और पक्षकारों के विद्वत वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने पर, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि राकेश कुमार की मृत्यु प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा महिंद्रा पिक-अप पंजीकरण संख्या HR-64-36291 को लापरवाही से चलाने के कारण हुई दुर्घटना में हुई चोटों के कारण हुई; प्रतिवादीगण संख्या 1 के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था और प्रतिवादीगण संख्या 2 के पास रूट परमिट की आवश्यकता नहीं थी और दावेदार मृतक का कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तक से संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे का भुगतान करने का हकदार था।

(5) न्यायाधिकरण ने मृतक की आयु लगभग 22 वर्ष निर्धारित की, उसकी आय का आकलन 5,157/- रुपये किया, भविष्य की संभावनाओं के लिए 50 प्रतिशत जोड़ा, व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50 प्रतिशत की कटौती की और दावेदार की आयु के अनुसार 11 के गुणक को लागू करके निर्भरता के नुकसान का आकलन रुपयेऽ 501600 किया ।हालाँकि, न्यायाधिकरण ने मृतक के नियोक्ता से दावेदार द्वारा प्राप्त 253469 रुपये की राशि में कटौती की और दावेदार को प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत की दर से लागत और ब्याज के साथ रुपये की राशि का हकदार ठहराया।

(6) पीड़ित महसूस करते हुए दावेदार ने मुआवजे में वृद्धि के लिए वर्तमान अपील दायर की है।

(7) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा संबोधित तर्क सुने हैं और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

(8) अपीलार्थी के वकील सरि राज कपूर मलिक ने तर्क दिया है कि मृतक राकेश कुमार की मृत्यु के कारण देय मुआवजे की राशि में से रुपये 253469 की कटौती नहीं की जा सकती है और न्यायाधिकरण ने इसमें कटौती करने में गलती की है। न्यायाधिकरण ने अंतिम संस्कार के खर्च और संपत्ति के नुकसान के लिए अल्प राशि का आदेश दिया और संतान संघ के नुकसान के लिए कोई राशि नहीं दी। न्यायाधिकरण ने ब्याज की कम दर का फैसला सुनाया।इसलिए, पुरस्कार को संशोधित किया जा सकता है और दिए गए मुआवजे को बढ़ाया जा सकता है।

(9) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी No.3-बिमा कंपनी के विद्वान वकील श्री अश्विनी तलवार और श्री जगजीत सिंह चतरथ ने तर्क दिया है कि न्यायाधिकरण ने कंप्यूटर से उत्पन्न वेतन पत्रों के आधार पर मृतक की आय का गलत आकलन 5,157/- रुपये किया है जो विधिवत साबित नहीं हुए थे और आय का आकलन अकुशल मजदूर को देय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत जोड़ने में गलती की क्योंकि मृतक के पास स्थायी नौकरी नहीं थी।मृतक के नियोक्ता से दावेदार द्वारा प्राप्त रुपये 253469 की राशि उसकी मृत्यु के लिए देय मुआवजे की राशि से कटौती के लिए उत्तरदायी थी और दावेदार मुआवजे की वृद्धि का हकदार नहीं है जो कम करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, मुआवजे में कमी करके पुरस्कार में संशोधन के साथ, अपील को खारिज किया जा सकता है।

(10) वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने पीडब्लू-1 सरि सरद संदीप, सहायक प्रबंधक (एचआर एंड एडमिन), युटाका ऑटोपार्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी (राजस्थान) द्वारा साबित वेतन पत्र Ex.P-1 से Ex.P-3 के आधार पर मृतक की आय का आकलन किया।न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की श्क्षक योगयता देखतेS हुये जिसने कक्षा 10+2 कि परिक्षा पास कि हुइ थी और टेड मे नियमित उमिदवार केS रूप मे टेड टरनर के परमाण पतर पी 17 और पी 16 के रोजगार और उसके द्वारा प्राप्त वेतन की सीमा पर अविश्वास करने का

कोई आधार नहीं है ।इस मौखिक और दस्तावेजी साक्षय को ध्यान में रखते हुए, जो लगभग अप्रकाशित और बिना चुनौती के चला गया था, मृतक के रोजगार और वेतन के बारे में न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है ताकि इसमें हस्तक्षेप किया जा सके ।हालांकि, इस दृष्टि से कि

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फूल सिंह बनाम विरेंद्र सिंह और अन्य के पैरा No.61 (iv) में की गई टिप्पणियां

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य में इसका निर्णय

1 और यह तथ्य कि मृतक के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी और वह केवल एक संविदात्मक कर्मचारी था, न्यायाधिकरण को भविष्य की संभावनाओं के लिए अपनी आय में अपने वेतन के 50 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत जोड़ना चाहिए था ।चूंकि मृतक कुंवारा था, इसलिए न्यायाधिकरण ने सही आकलन किया कि दावेदार की निर्भरता उसकी वार्षिक आय का 50 प्रतिशत है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार व्यय पैरा No.15

सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और एएनआर 2।

(11) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में राष्ट्रीय बीमा

कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य 3 ने देखा कि

मृतक को गुणक को लागू करने का आधार होना चाहिए और मृतक या दावेदार या माता-पिता, जो भी अधिक हो, की आयु के आधार पर गुणक के आवेदन के बारे में विचार को खारिज कर दिया जाता है ।

(12) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अनुच्छेद No.21 में कहा कि

श्रीमती में निर्णय । सारला वर्मा का मामला (सुप्रा) निम्नानुसार है:-

“इसलिए हमारा मानना है कि उपयोग किए जाने वाले गुणक को होना चाहिए

जैसा कि ऊपर की तालिका के कॉलम (4) में उल्लेख किया गया है (सुसम्मा थॉमस, त्रिलोक चंद्र और चार्ली को लागू करके तैयार किया गया), जो 18 (15 से 20 और 21 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लिए) के ऑपरेटिव गुणक के साथ शुरू होता है, हर पांच साल के लिए एक इकाई घटाई जाती है, जो 26 से 30 वर्ष के लिए एम-17,31 से 35 वर्ष के लिए एम-16,36 से 40 वर्ष के लिए एम-15,41 से 45 वर्ष

के लिए एम-14 और 46 से 50 वर्ष के लिए एम-13 है, फिर हर पांच साल के लिए दो इकाइयों से घटाया जाता है, यानी 51 से 55 वर्ष के लिए एम-11,56 से 60 वर्ष के लिए एम-9,61 से 65 वर्ष के लिए एम-7 और

66 70 साल के लिये एम 5।"

(13) चूंकि मृतक की मृत्यु के समय उसकी आयु लगभग 22 वर्ष थी, इसलिए न्यायाधिकरण को मुआवजे की राशि के आकलन के लिए 11 के बजाय 18 का गुणक लागू करना आवश्यक था।

(14) यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि पीड़ित के आश्रितों द्वारा उसके नियोक्ता से प्राप्त अनुग्रह राशि उसकी मृत्यु के लिए एम. वी. अधिनियम के तहत देय मुआवजे से कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है।इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है।

नगर निगम और अन्य बनाम श्रीमती। अजीत कौर और

अन्य 4 और में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ds निर्णय सेबेस्टियन लाकड़ा

और अन्य बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और

अन्य 5 परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण को दावेदार को देय मुआवजे में से मृतक के नियोक्ता से दावेदार द्वारा प्राप्त रुपये की राशि में कटौती करने में भौतिक अनियमितता के लिए अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए।

(15) न्यायाधिकरण ने केवल अंतिम संस्कार के खर्च और संपत्ति के नुकसान के लिए Rs.10,000/- की राशि का आदेश दिया और संतान संघ के लिए कोई राशि नहीं दी।

(16) प्रणय सेठी के मामले में (सुप्रा) इसके अनुच्छेद No.61 (viii) में

निर्णय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उचित आंकड़े

पारंपरिक प्रमुख, अर्थात्, संपत्ति का नुकसान, संघ का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च क्रमशः Rs.15,000/-, Rs.40,000/- और Rs.15,000/- होना चाहिए।

(17) प्रणय सेठी के मामले में (सुप्रा) माननीय सर्वोच्च न्यायालय

उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त राशि को हर तीन साल में 10 प्रतिशत की दर से

बढ़ाया जाना चाहिए।उपरोक्त अवलोकन के परिणाम के रूप में

पारंपरिक आधार पर आंकड़ों में वृद्धि के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय

भविष्य में उत्पन्न होने वाले मामलों में मुआवजे के मूल्यांकन के लिए हर तीन साल में 10 प्रतिशत की दर से, पारंपरिक शीर्ष पर आंकड़े हर तीन साल के लिए मुआवजे के मूल्यांकन के लिए हर तीन साल के लिए 10 प्रतिशत की दर से कमी के लिए उत्तरदायी जो पुरव मे हुआ हो।

(18) मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम @चुहरू राम और अन्य 6 माननीय सर्वोच्च न्यायालय

स्पष्ट किया कि कानूनी भाषा में 'कंसोर्टियम' एक व्यापक शब्द है जिसमें 'स्पौसल कंसोर्टियम', 'पेरेंटल कंसोर्टियम' और 'फिलियल कंसोर्टियम' शामिल हैं और प्रत्येक को नुकसान के लिए Rs.40,000/- का मुआवजा दिया जाता है।

मृतक के पिता और बहन को संतान संघ।हालांकि, पीठ ने अपने फैसले के पैरा संख्या 8.7 में कहा कि संघ के नुकसान के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को नियंत्रित किया जाएगा -

'संघ के नुकसान' के तहत मुआवजा देने के सिद्धांत

प्रनय सेठी के मामले (सुप्रा) में निर्धारित।(19) मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मामले (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों और देने के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए

माननीय द्वारा निर्धारित पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजा

सर्वोच्च न्यायालय ने ऊपर निर्दिष्ट प्रणय सेठी के मामले (सुप्रा) में, मृतक के दावेदार-पिता को संतान संघ के नुकसान के लिए Rs.32,000/- और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए Rs.12,000/- और संपत्ति के नुकसान के लिए Rs.12,000/- का मुआवजा देने का अधिकार होगा।

(20) तदनुसार, राकेश कुमार की मृत्यु के कारण दावेदार को देय मुआवजे पर निम्नानुसार फिर से काम किया जाता है:-

श्री. नहीं	मुखिया।	क्षतिपूर्ति
	1 मृतक की मासिक आय Rs.5157-प्रति	

	माह	
	2 40 प्रतिशत की दर से भविष्य की संभावना को जोड़ने के बाद आय	Rs.5157 + Rs.2063=Rs.7220 -
	3 व्यक्तिगत खर्चों के कारण एक चौथाई की कटौती	
	4 निर्भरता का नुकसान	Rs.3610 * x12x18 = 7,79,760 -
	6 अंतिम संस्कार का खर्च	Rs.12,000/-
	7 पति-पत्नी, माता-पिता और संतान संघ के नुकसान के लिए देय मुआवजा	Rs.32,000/-
	8 संपत्ति का नुकसान	Rs.12,000
	कुल मुआवजा	रु. 8,35,760

(21) वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से पूरी राशि की प्राप्ति तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसे अपर्याप्त होने के लिए चुनौती दी गई है और जो सवाल उठता है वह यह है कि ब्याज की उचित दर क्या होगी।

(22) पुट्टम्मा और अन्य बनाम के. एल. नारायण रेड्डी

और अन्य 7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 60 में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"अबाती बेजबरूआ बनाम उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और

इस न्यायालय मे अन्य (2003) 3

एस. सी. सी. 148 ने देखा कि न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय द्वारा ब्याज की अलग-अलग दर दी जा रही है।उक्त मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ब्याज की दर केवल

और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित और मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अपनाई जा

रही नीति, मामला कितने समय तक लंबित है, नुकसान जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए।

जीवन का आनंद लेना आदि।"

(23) सुपे देई और अन्य बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य 8 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9 प्रतिशत प्रति

मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति मामलों में दिए जाने वाले ब्याज की उचित दर वर्ष होगी।सुबे सिंह और अन्य

बनाम श्याम सिंह (मृत) और अन्य 9 प्रतिशत की ब्याज दर

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए वर्ष को संशोधित किया गया था

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 9 प्रतिशत प्रति वर्ष।

(24) उपर्युक्त संदर्भित न्यायिक उदाहरणों में टिप्पणियों, प्रचलित ब्याज की वाणिज्यिक दर, सावधि जमा प्राप्तियों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुमत ब्याज दर और अन्य प्रासंगिक कारकों को देखते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा दी गई 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर को संशोधित करके 9 प्रतिशत प्रति वर्ष करना उचित होगा।

(25) प्रत्यर्थी No.3-बिमा कंपनी के वकील श्री अश्विनी तलवार और श्री जगजीत सिंह चतरथ ने तर्क दिया है कि मृतक दो पिछली सीट पर सवार लोगों के साथ मोटरसाइकिल चला रहा था और दुर्घटना में योगदान देने में अंशदायी लापरवाही का दोषी था।न्यायाधिकरण को मुआवजे को 50 के अनुपात में विभाजित करना चाहिए था:50.मृतक की अंशदायी लापरवाही के कारण मुआवजे के विभाजन के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्णय लिया जा सकता है, भले ही प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपील या प्रति-आपत्ति के अभाव में भी।मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्तियों को ले जाने के कारण मृतक की ओर से अंशदायी लापरवाही को देखते हुए, मुआवजे के विभाजन द्वारा पुरस्कार में संशोधन किया जा सकता है।

(26) दूसरी ओर, अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री राज कपूर मलिक ने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने कोई अपील या प्रति-आपत्ति दायर नहीं की है और इसके अभाव में मृतक की ओर से दो पिछली सिट सवारों को ले जाने के कारण

अंशदायी लापरवाही के सवाल और उसी के मद्देनजर मुआवजे के विभाजन पर सी. पी. सी. के आदेश 41 नियम 33 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके निर्णय नहीं लिया जा सकता है। उनकी दलीलों के समर्थन में वकील के लिए सीखा

9 2018 (2) आर. सी. आर (सिविल) 131 (एससी)

अपीलार्थी ने प्रकाश और अन्य बनाम मंडल प्रबंधक और अन्य **10** में टिप्पणियों पर भरोसा रखा है

(27) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि अन्यथा भी, दोपहिया वाहन पर तीन सवारॊ के साथ सवारी करना अपने आप में अंशदायी लापरवाही नहीं है, हालांकि यह एम. वी. अधिनियम के तहत एक अपराध हो सकता है जो दंडात्मक परिणामों की गारंटी देता है।प्रतिवादीगण ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया कि मृतक द्वारा दो पिलियन सवारों के साथ मोटरसाइकिल चलाने का किसी भी तरह से दुर्घटना में योगदान था।इसलिए, मृतक की ओर से अंशदायी लापरवाही के प्रमाण के अभाव में, मुआवजे के विभाजन का सवाल ही नहीं उठा।

(28) वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपनी मोटरसाइकिल पर दो पिछली सिट सवारों को ले जाने के कारण मृतक की ओर से अंशदायी लापरवाही के आधार पर कोई अपील या प्रति-आपत्ति दायर नहीं की है, जिसमें उसकी मृत्यु के लिए देय मुआवजे के परिणामी विभाजन की मांग की गई है।

(29) रंजना प्रकाश के मामले (सुप्रा) में यह कहा गया था कि

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा संख्या 8 में कहा है:- "जहाँ मुआवजा की मात्रा को चुनौती देते हुए अपील दायर की जाती है

चाहे कोई भी अपील दायर करे, उच्च न्यायालय के लिए उपयुक्त तरीका तथ्यों की जांच करना और प्रासंगिक सिद्धांतों को लागू करके, न्यायसंगत मुआवजे का निर्धारण करना है।यदि उसके द्वारा निर्धारित मुआवजा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे से अधिक है, तो उच्च न्यायालय अपील की अनुमति देगा, यदि यह दावेदारों द्वारा है और अपील को खारिज कर देगा, यदि यह मालिक/बीमाकर्ता द्वारा है।इसी तरह, यदि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे से कम है, तो उच्च न्यायालय वृद्धि के लिए दावेदारों की

किसी भी अपील को खारिज कर देगा, लेकिन मालिक/बीमाकर्ता द्वारा कटौती के लिए किसी भी अपील की अनुमति देगा ।उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से मुआवजे को कम करने के लिए मालिक/बीमाकर्ता की अपील में मुआवजे को नहीं बढ़ा सकता है, और न ही यह मुआवजे को बढ़ाने की मांग करने वाले दावेदारों की अपील में मुआवजे को कम कर सकता है।

(जोर दिया गया)।

(30) इस तरह की अपील/प्रति-आपत्तियों के अभाव में अंशदायी लापरवाही और मुआवजे के परिणामी विभाजन के प्रश्नों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है और दावेदार को देय मुआवजे को सी. पी. सी. के आदेश 41 नियम 33 में पुनः परकिरया द्वारा कम नहीं किया जा सकता है।

(31) अन्यथा भी जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या दो पिछलॅे सवारों को ले जाना अपने आप में अंशदायी लापरवाही है या नहीं ।एम. वी. अधिनियम की धारा 128 (1) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें दो पहियों वाली मोटर साइकिल के चालक को अपने अलावा एक से अधिक व्यक्तियों को ले जाने से प्रतिबंधित किया गया है, मोटर साइकिल पर दो पिछलॅेऽ सवारों को ले जाना एम. वी. अधिनियम की धारा 177 के तहत दंडनीय अपराध है। हालांकि, यह सवाल कि क्या यह अंशदायी लापरवाही है,यह विवाद मुक्त नहीं है।

विवाद ।**2011** के एफ**.** ए**.** ओ**. No.3760** में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बनाम बलविंदर सिंह **26.05.2011** पर फैसला **esa** किया।

इस न्यायालय की समन्वित पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि दोपहिया वाहन पर तीन सवारी के साथ सवारी करना अंशदायी लापरवाही नहीं है ।हालांकि, एफ. ए. ओ. में

2010 का सं**. 6550** जिसका शीर्षक अंग्रेजी देवी और अन्य बनाम जय प्रकाश है।

और अन्य लोगों ने इसके लिए एक माननीय समन्वय पीठ **us** निर्णय लिया और

न्यायालय ने यह विचार रखा कि ट्रिपल राइडिंग अपने आप में अंशदायी लापरवाहि a है।

माननीय समन्वय के विचारों के इस टकराव के कारण

इस न्यायालय की पीठों द्वारा इस मामले को बड़ी पीठ को भेजा गया था।

इस न्यायालय की माननीय समन्वय पीठ ने दिनांक 07.03.2014 के आदेश के माध्यम से

2012 (ओ एंड एम) के एफ. ए. ओ. **No.2218** में सोना देवी और अन्य शीर्षक

बनाम रमेश कुमार और अन्य मेंsa निर्णय लिया गया।हालाँकि, वर्तमान अपील के निर्णय को बड़ी पीठ के पास संदर्भ के लंबित होने के कारण स्थगित नहीं किया जा सकता है और अपील का निर्णय टकटकी निर्णय के सिद्धांत के अनुसार प्रचलित कानूनी स्थिति के आधार पर किया जाना है **2011** का एफ. ए. ओ. **No.3760** ।में लिया गया दृश्य

जिसका शीर्षक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बनाम

बलजिनदर सिंह मे निर्णय लिया कि 26.05.2011 बाध्यकारी मिसाल का गठन तब तक करेगा जब तक कि इसे एक बड़ी पीठ द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता है और दोपहिया वाहन पर ट्रिपल सवारी अपने आप में अंशदायी लापरवाही नहीं होगी। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने के संबंध में उठाए गए इसी तरह के सवाल पर

सरस्वती पलारिया बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड **2019**

ए. सी. जे. 42 माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाए गाड़ी चलाना

चालक को दंडात्मक दायित्व के लिए उजागर कर सकता है लेकिन उस आधार पर अंशदायी लापरवाही का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।(32) वर्तमान मामले में, यह माना जाता है कि मृतक अपनी मोटरसाइकिल पर दो पिछली सीट पर सवार विक्रम और तारसेम को ले जा रहा था।हालांकि, पी. डब्ल्यू.-5 विक्रम, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे सवारों में से एक, विशेष रूप से

अपदस्थ किया कि प्रतिवादी नंबर 1 महिंद्रा पिक-अप को जल्दबाजी और लापरवाही से चला रहा था और सड़क के गलत तरफ आकर उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और दुर्घटना के लिए अकेले प्रतिवादी नंबर 1 जिम्मेदार था। प्रतिवादीगण ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया कि मृतक, जो

मोटरसाइकिल चला रहा था, ने किसी भी तरह से दुर्घटना में योगदान दिया था। इन परिस्थितियों में, केवल यह तथ्य कि तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे थे, अपने आप में इस निष्कर्ष का समर्थन/औचित्य नहीं देता है कि मृतक-मोटरसाइकिल का चालक राकेश कुमार दुर्घटना के कारण अंशदायी लापरवाही का दोषी था, जो केवल प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा महिंद्रा पिक-अप की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ था।

(33) उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि दावेदार याचिका दायर करने की तारीख से प्राप्ति तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लागत और ब्याज के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तक रुपये 835760 के मुआवजे का भुगतान करने का हकदार है।न्यायाधिकरण द्वारा दावेदार को दिए गए रु. 2,58,131 की राशि उपरोक्त गणना की गई राशि में से कटौती के लिए उत्तरदायी होगी।दावेदार को मुआवजे की राशि के वितरण के तरीके के बारे में न्यायाधिकरण के निर्देश बढ़े हुए मुआवजे के वितरण पर भी लागू होंगे।

(34) न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 08.08.2011 के निर्णय में उपरोक्त संशोधनों के साथ वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है।

शुभरीत कौर

असवीकरण:- सथानिय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिये है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अनय उदेशय के लिये इसका उपयोग नही किया जा सकता ।सभी वयवहारिक और अधिकारिक उदेशयो के लिये निर्णय का अगरेजी सनसकरण परमाणिक होगा और निषपादन और कारयानयन के उदेशयो के लिये उपयुकत रहेगा ।

राज कुमार

अनुवादक